IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत और क्वाड: हिंद–प्रशांत क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग का विश्लेषण

रूचि(परास्नातक)

राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएचपी)
सप्त सिंधु परिसर, देहरा – 177101 धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, भारत

सारांश

21वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में वैश्विक शक्ति-संतुलन में तीव्र परिवर्तन हुए, जिनका सबसे गहरा प्रभाव हिंद–प्रशांत क्षेत्र में देखने को मिला। इस क्षेत्र ने न केवल रणनीतिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक और भू-राजनीतिक रूप से भी एक नई पहचान प्राप्त की। इसी परिप्रेक्ष्य में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने क्वाड मंच के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा और स्थिरता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया।यह शोध-पत्र क्वाड की भूमिका का सैद्धांतिक और कार्यप्रणालीगत विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें शक्ति-संतुलन सिद्धांत, उदारवाद तथा नव–संस्थागत दृष्टिकोणों के माध्यम से इसके उभार को समझने का प्रयास किया गया है। अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि क्वाड केवल एक सुरक्षा तंत्र नहीं है, बल्कि यह एक मूल्य-आधारित रणनीतिक सहयोग मंच के रूप में उभर रहा है, जो लोकतंत्र, पारदर्शिता और नियम-आधारित व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। लेख में यह भी विश्लेषित किया गया है कि चीन की आक्रामक नीतियों और दक्षिण चीन सागर में उसके विस्तारवादी दृष्टिकोण ने इस मंच के निर्माण और सुदृढ़ीकरण को कैसे प्रभावित किया। साथ ही, यह शोध भारत की एक्ट ईस्ट नीति के साथ क्वाड की सामंजस्यपूर्ण भूमिका का भी अध्ययन करता है। अंततः, यह अध्ययन इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करता है कि क्या क्वाड भविष्य में एक औपचारिक सुरक्षा गठबंधन के रूप में विकसित हो सकेगा, और इसमें भारत की भूमिका कितनी निर्णायक सिद्ध होगी।

मुख्य शब्द: क्वाड, भारत, हिन्द–पैसिफिक, रणनीतिक सहयोग, शक्ति-संतुलन, विदेश नीति, क्षेत्रीय सुरक्षा, बहुपक्षवाद, एक्ट ईस्ट नीति, हिन्द–पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव

21वीं सदी की शुरुआत में विश्व की शक्ति-संतुलन व्यवस्था में बड़े बदलाव हुए। इन परिवर्तनों से अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदली और हिंद–प्रशांत क्षेत्र को नई रणनीतिक पहचान मिली। इसी संदर्भ में 21 जनवरी 2025 को वॉशिंगटन डी.सी. में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में चारों देशों ने स्वतंत्र और खुले हिंद–प्रशांत क्षेत्र को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में कानून के शासन, लोकतांत्रिक मूल्यों और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा पर विशेष जोर दिया गया। यह माना गया कि अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन, आर्थिक अवसरों का विस्तार, और शांति एवं स्थिरता ही इस क्षेत्र की प्रगति का आधार हैं।

हालाँकि, इसी बीच क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियाँ चिंता का विषय बनी हुई हैं। दक्षिण चीन सागर में उसका सैन्य विस्तार और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित करने की नीति भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए चुनौती बन गई है। इन परिस्थितियों में "क्वाड" मंच का विचार सामने आया, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देना है। क्वाड ने मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद 4 अप्रैल 2025 को क्वाड देशों ने संयुक्त वक्तव्य जारी किया और प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही, 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की मानवीय सहायता देने का वादा किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि क्वाड की शुरुआत 2004 के हिंद महासागर सुनामी के दौरान हुई, जब इन देशों ने एक साथ मिलकर राहत कार्य किया था। आज भी क्वाड आसियान देशों और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों को बेहतर बनाने में सहयोग कर रहा है।

हिंद–प्रशांत की अवधारणा अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीतियों में प्रमुख स्थान रखती है। इसे एक नियम-आधारित व्यवस्था और चीन की बढ़ती शक्ति के प्रति सामूहिक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। अभी तक इस क्षेत्र में कोई औपचारिक संस्थागत ढाँचा नहीं बना है, लेकिन भविष्य में इसकी सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि क्या यह स्थायी संरचना ले पाता है या नहीं (हे और फेंग, 2020)।

भारत के लिए क्वाड का महत्व कई स्तरों पर है-सुरक्षा, आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक सभी दृष्टियों से। यह मंच भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिन्द–पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव से जुड़ा है और भारत को अपने क्षेत्रीय साझेदारों के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर देता है।

फिर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं-क्या क्वाड वास्तव में एक सुरक्षा गठबंधन है? क्या यह चीन के प्रभाव को संतुलित कर पाएगा? और इस मंच में भारत की भूमिका कितनी निर्णायक होगी? इन्हीं प्रश्नों के उत्तरों की खोज इस शोध का मुख्य उद्देश्य है।

सैद्धांतिक परिप्रेक्ष में:

आधुनिक यथार्थवाद के प्रमुख विचारक **हंस जे. मॉर्गेंथाउ** (1948) माने जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति "पॉलिटिक्स अमंग नेशन्स" को यथार्थवाद की आधारशिला माना गया है। मॉर्गेंथाउ के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय राजनीति सत्ता की खोज और राष्ट्रीय हितों की निरंतरता पर आधारित होती है। राष्ट्र-राज्य अपने हितों की पूर्ति के लिए ही गठबंधन करते हैं। इसी दृष्टिकोण से भारत ने क्वाड को एक रणनीतिक मंच के रूप में स्वीकार किया है, ताकि हिंद–प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित किया जा सके। मॉर्गेंथाउ के यथार्थवाद में **शक्ति संतुलन** एक केंद्रीय विचार है। भारत क्वाड के माध्यम से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्षेत्र में सैन्य और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहा है।अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में संरचनावाद एक अपेक्षाकृत नया सिद्धांत है। यह सिद्धांत यह बताता है कि राज्यों के बीच संबंध केवल शक्ति या आर्थिक हितों पर आधारित नहीं होते, बल्कि विचारों, मान्यताओं और पहचान पर भी निर्भर करते हैं।

संरचनावाद के दृष्टिकोण से समझा जाए तो, इसके प्रमुख प्रवर्तक अलेक्जेंडर वेन्ड्ट (1992) हैं। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति "अनार्की ईस व्हाट स्टेट मेक ऑफ़ इट " में यह तर्क दिया कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की प्रकृति अराजक नहीं होती, बल्कि वही बनती है जो राज्य स्वयं उससे बनाते हैं। अर्थात्, अंतरराष्ट्रीय राजनीति केवल भौतिक शक्ति से नहीं, बल्कि साझा विचारों और आपसी विश्वास से निर्मित होती है। इसी दृष्टि से, क्वाड को केवल एक सामरिक गठबंधन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह एक ऐसा मंच है जो साझा मूल्यों और लोकतांत्रिक विश्वासों पर आधारित है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश एक समान सोच रखते हैं-यानी कि वे स्वतंत्र, समावेशी और नियम-आधारित हिन्द–पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण में विश्वास करते हैं।

भारत की भूमिका इस दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखती है। भारत स्वयं को एक जिम्मेदार क्षेत्रीय *शक्ति* के रूप में देखता है, जो न केवल सुरक्षा और स्थिरता में योगदान देना चाहता है, बल्कि सहयोग, संवाद और पारदर्शिता जैसे आदर्शों को भी आगे बढ़ाना चाहता है। यही विचार भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिन्द–पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव में भी दिखाई देता है। अंततः, संरचनावादी दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि क्वाड की नींव केवल शक्ति-संतुलन या सुरक्षा चिंताओं पर नहीं, बल्कि साझा विचारों और मान्यताओं पर टिकी है।

शोध पद्धति

इस अध्ययन में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की शोध-पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले, गुणात्मक स्रोतों के रूप में सरकारी दस्तावेज़, नीतिगत रिपोर्टें और अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रकाशित विश्लेषणात्मक अध्ययन को शामिल किया गया है।साथ ही, भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी नीति-दस्तावेज़, श्वेत पत्र और वार्षिक रिपोर्टें भी अध्ययन का आधार बनी हैं। इसके अतिरिक्त, इस शोध में जर्नल ऑफ द इंडियन ओशन रीजन और जादवपुर जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन्स जैसी

प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों को भी उपयोग में लाया गया है।मात्रात्मक स्रोतों में द पैसिफिक रिव्यू, इंटरनेशनल सिक्योरिटी जैसे अंतरराष्ट्रीय शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और अन्य थिंक टैंकों द्वारा जारी रिपोर्टों को भी अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। यह शोध मिश्रित पद्धति पर आधारित है, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के डेटा का उपयोग किया गया है। अंततः, अध्ययन का दृष्टिकोण पूरी तरह से तटस्थ, सैद्धांतिक और प्रमाण-आधारित है। इसमें थिंक टैंक रिपोर्टों, समाचार विश्लेषणों और अकादमिक लेखों से प्राप्त तथ्यों की समीक्षा की गई है, ताकि निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय बने रहें।

क्वाड की पृष्ठभूमि

क्वाड, जिसे प्रारंभ में चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के रूप में जाना जाता था, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रणनीतिक कूटनीतिक साझेदारी है। इसकी शुरुआत दिसंबर 2004 में हुई, जब ये चार देश हिंद महासागर में आई भीषण सुनामी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए एक तदर्थ समूह के रूप में एकजुट हुए। जनवरी 2005 में राहत अभियान समाप्त हो जाने के बाद भी इन देशों के बीच अधिक औपचारिक साझेदारी की दिशा में प्रयास जारी रहे। साल 2007 में, मनीला (फिलीपींस) में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के अवसर पर क्वाड की पहली अनौपचारिक बैठक संपन्न हुई। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण कदम था, किंतु राजनयिक दबावों और विशेषकर चीन की आपत्तियों के कारण 2008 में यह समूह निष्क्रिय हो गया।

इसके बाद, क्षेत्रीय परिस्थितियों में हुए परिवर्तनों और हिंद–प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता ने सदस्य देशों को पुनः सहयोग के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप, 2017 में क्वाड को पुनर्जीवित किया गया। इस बार इसका उद्देश्य केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि व्यापक रणनीतिक, आर्थिक और समुद्री सहयोग को भी शामिल करता था। उसी वर्ष मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान चारों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई, जिसने इस मंच को नई गति प्रदान की। अगले कुछ वर्षों में क्वाड ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थानों के माध्यम से नीति समन्वय, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय स्थिरता को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसने हिंद–प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व बनाए रखने के लिए साझा मूल्यों और नियम-आधारित व्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य किया (सरन आदि, 2024)।

पिछले चार वर्षों में क्वाड नेताओं ने कुल **छह बार** बैठकें की हैं, जिनमें से दो बैठकें वर्चुअल माध्यम **से** आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की आठ बार बैठक हो चुकी है, जिनमें सबसे हालिया बैठक **जुलाई** 2025 में टोक्यो में संपन्न हुई। इन बैठकों में चारों देशों ने यह संकल्प दोहराया कि वे हिंद–प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व बनाए रखने के लिए सहयोग को और मजबूत करेंगे। प्रत्येक क्वाड सरकार ने यह प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि वह अपनी-अपनी बजटीय प्रक्रियाओं के माध्यम से हिंद–प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की प्राथमिकताओं के लिए सुदृढ़ वित्तीय सहयोग सुनिश्चित करेगी। साथ ही,

ये देश अपने-अपने विधानमंडलों के साथ समन्वय स्थापित कर अंतर-संसदीय आदान–प्रदान को बढ़ाने और विभिन्न हितधारकों को क्वाड के समकक्षों के साथ जुड़ाव के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं।

क्वाड की विभिन्न कार्य-समूह और **पहलें** क्षेत्रीय भागीदारों के साथ करीबी परामर्श के आधार पर संचालित होती हैं। इनमें स्वास्थ्य सुरक्षा**,** जलवायु सहनशीलता**, और** बुनियादी ढाँचे के विकास को शीर्ष प्राथमिकताओं में रखा गया है (सरन आदि, 2024)।

भारत की भूमिका

भारत आज हिन्द–प्रशांत क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। इसकी भूमिका इसकी भौगोलिक स्थिति, रणनीतिक दृष्टिकोण और लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई है। भारत की "एक्ट ईस्ट नीति", समुद्री और नौसैनिक सहयोग की पहलें, तथा क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय भागीदारी ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ बना दिया है। भारत न केवल समुद्री व्यापार और आपूर्ति शृंखलाओं की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, बल्कि वह छोटे देशों के साथ मानवीय सहायता, आपदा राहत, और विकास सहयोग जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय योगदान दे रहा है। इन पहलों ने भारत की छवि एक जिम्मेदार और सहयोगी शक्ति के रूप में सुदृढ़ की है।

वर्तमान समय में भारत को विश्व राजनीति में एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। यह भूमिका विशेष रूप से अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता से प्रभावित हिन्द–प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक संरचना में निर्णायक बन गई है। यह क्षेत्र केवल प्रतिस्पर्धा का केंद्र नहीं, बल्कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों द्वारा साझा मूल्यों– स्वतंत्रता, खुलापन और पारदर्शिता–को सशक्त बनाने का मंच भी है। चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, इन देशों ने उदार, नियम–आधारित और समावेशी व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया है। हालांकि भारत ने इस उदार पहचान को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया है, उसने इसे अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं और स्वायत्त विदेश नीति के अनुरूप ढालने का प्रयास किया है। भारत का दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि उसकी विदेश नीति केवल किसी गठबंधन की छाया में नहीं, बल्कि अपने स्वतंत्र निर्णय और क्षेत्रीय हितों के अनुरूप विकसित होती है।

भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि अक्सर अन्य क्वाड देशों से अलग रही है। यही कारण है कि भारत का दृष्टिकोण भविष्य में हिन्द–प्रशांत क्षेत्र के शक्ति–संतुलन को प्रभावित कर सकता है। यद्यपि भारत एक उदार और सहयोगी व्यवस्था का समर्थन करता है, परंतु इसके कार्यान्वियन में उसे तीन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है – पहली, समुद्री क्षेत्र में सीमित नौसैनिक क्षमता; दूसरी, उत्तर में चीन के साथ अस्थिर संबंध; और तीसरी, पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान तथा ईरान को लेकर भारत और अमेरिका के बीच मतभेद। ये सभी भारत की व्यापक क्षेत्रीय भूमिका के समक्ष व्यावहारिक बाधाएँ उत्पन्न करती हैं।

इसके बावजूद, यदि भविष्य में भारत और चीन के बीच टकराव की स्थिति बनती है, तो भारत को अपनी सैन्य और तकनीकी क्षमताओं को और सुदृढ़ करना होगा। ऐसी स्थिति में भारत अमेरिका और अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर अधिक रणनीतिक गठजोड़ का हिस्सा बन सकता है। इसके अतिरिक्त, दक्षिण चीन सागर में भारत की ऊर्जा परियोजनाएँ और व्यापारिक हित उसकी सक्रिय उपस्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। भारत की "लुक ईस्ट नीति" को आगे बढ़ाते हुए "एक्ट ईस्ट नीति" ने भारत की रणनीतिक पहुंच को प्रशांत क्षेत्र तक विस्तारित किया है। भारत दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है और वहाँ नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयासों में भाग ले रहा है। अंततः कहा जा सकता है कि भारत हिन्द–प्रशांत क्षेत्र में एक उदार और समावेशी व्यवस्था का समर्थन करता है, किंतु वह इसे अपनी सुरक्षा, स्वायत्तता और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए पुनर्परिभाषित करने का प्रयास कर रहा है। भारत की यही नीति उसे एक विशिष्ट, संतुलित और जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित करती है, जो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की दिशा में ठोस योगदान दे रही है (पंत और रेज, 2018)।

भारत का दृष्टिकोण : 2014 के बाद का परिप्रेक्ष्य

सन् 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत ने हिंद–प्रशांत क्षेत्र को अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं में एक प्रमुख स्थान प्रदान किया है। इस अवधि में भारत का दृष्टिकोण पहले की तुलना में अधिक सक्रिय, समावेशी और दूरदर्शी बन गया है। पहले जहाँ भारत की "लुक ईस्ट नीति" केवल पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों तक सीमित थी, वहीं अब "एक्ट ईस्ट नीति" के माध्यम से भारत ने इस नीति को एक व्यापक रणनीतिक और सुरक्षा दृष्टिकोण से जोड़ दिया है।

भारत ने हिंद–प्रशांत क्षेत्र के प्रति जो नया दृष्टिकोण अपनाया है, वह समावेशिता और पारस्परिक सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित है। इस नीति का मूल उद्देश्य किसी भी देश को अलग–थलग करने के बजाय सभी देशों को सहयोग की भावना से जोड़ना है। भारत का यह मानना है कि हिंद–प्रशांत क्षेत्र में सभी विवादों का समाधान शांतिपूर्ण और संवाद–आधारित तरीकों से होना चाहिए, न कि बल प्रयोग या दबाव की नीति से। भारत इस बात पर विशेष बल देता है कि क्षेत्र में किसी भी बड़ी शक्ति को छोटे देशों को अपनी रणनीतिक चालों का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। इसके विपरीत, सभी देशों को समान अधिकार और निर्णय–स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। भारत का यह भी दृढ़ मत है कि हिंद–प्रशांत क्षेत्र में नौवहन और समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि कोई भी देश अपने आर्थिक या सामरिक हितों के लिए दूसरों पर अपनी इच्छा न थोप सके। भारत का एक और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि क्षेत्र की समस्याओं और विवादों का समाधान यथासंभव स्थानीय स्तर पर, अर्थात क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए। भारत नहीं चाहता कि बाहरी शक्तियाँ इन आंतरिक या क्षेत्रीय मुद्दों में हस्तक्षेप करें, क्योंकि इससे स्थानीय संतुलन और स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।

इसके साथ ही, भारत यह भी मानता है कि समुद्री मार्गों और अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों से संबंधित सभी नियमों और संधियों का सभी देशों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कानूनों, विशेषकर समुद्री कानूनों का पालन, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की आधारशिला माना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में "सागर दृष्टि" यानी "सुरक्षा और विकास सभी के लिए" के सिद्धांत को आगे बढ़ाया, जो हिंद–प्रशांत में भारत के दृष्टिकोण का नैतिक और रणनीतिक आधार बन गया है। इस प्रकार, भारत की नीति केवल सामरिक प्रतिस्पर्धा पर नहीं, बल्कि सहयोग, समानता और साझा विकास पर आधारित एक संतुलित क्षेत्रीय व्यवस्था की दिशा में अग्रसर है।

चुनौतियाँ

क्वाड की रणनीति और सक्रियता के सामने कई प्रमुख चुनौतियाँ हैं।पहली चुनौती सदस्य देशों के अलग-अलग रणनीतिक हितों से जुड़ी है। उदाहरण के लिए, अमेरिका का दृष्टिकोण चीन के प्रति आक्रामक है, जबकि भारत परंपरागत रूप से रणनीतिक संतुलन बनाए रखने का पक्षधर रहा है। ऐसे में क्वाड की नीतियों में सामंजस्य और एकरूपता बनाए रखना कठिन हो जाता है।दूसरी चुनौती क्षेत्रीय देशों की संवेदनशीलता से संबंधित है। कई देश क्वाड को "एंटी–चाइना गठबंधन" के रूप में देखते हैं, जिससे आसियान जैसे संगठनों के साथ समन्वय प्रभावित हो सकता है। तीसरी चुनौती सैन्य सहयोग की सीमाओं से जुड़ी है। अभी तक क्वाड का कोई स्थायी सैन्य ढांचा नहीं है, जिससे इसे नाटो जैसे प्रभावशाली संगठन के समान खड़ा करना कठिन हो जाता है। इन सबके बावजूद, क्वाड का महत्व कम नहीं हुआ है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सदस्य देश आपसी मतभेदों को दूर करके कितनी प्रभावी रणनीतिक एकता और क्षेत्रीय सहयोग स्थापित कर पाते हैं|

समुद्री साइबर सुरक्षा

हिंद–प्रशांत क्षेत्र में समुद्री साइबर सुरक्षा का प्रश्न आज भी अस्पष्ट बना हुआ है। इस क्षेत्र में देशों की भागीदारी का स्वरूप अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही स्तरों पर स्पष्ट नहीं है। वैश्विक साइबर सुरक्षा परिदृश्य में समुद्री उद्योग अन्य उद्योगों की तुलना में लगभग बीस वर्ष पीछे माना जाता है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में साइबर हमलों की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं और यह अब एक गंभीर वैश्विक चिंता का विषय बन चुकी है।

सन् 2020 में समाप्त तीन वर्षों की अवधि के दौरान परिचालन प्रौद्योगिकी (ओ.टी.) प्रणालियों पर साइबर हमलों में लगभग नौ सौ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके बावजूद, समुद्री उद्योग पर होने वाले अधिकांश हमले रिपोर्ट नहीं किए जाते। यहाँ तक कि जिन घटनाओं की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, वे भी बहुत सीमित हैं। इस कारण हिंद–प्रशांत क्षेत्र से कुछ ही चुनिंदा घटनाएँ सामने आती हैं, जो इस क्षेत्र में साइबर खतरों की विविधता और जटिलता को दर्शाती हैं।

इसी संदर्भ में सन् 2011 की एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख किया जा सकता है, जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइंस जो ईरान की सरकारी स्वामित्व वाली शिपिंग कंपनी है, के सूचना तंत्र को हैक कर लिया गया था। इस साइबर हमले में

सरकारी अधिकारियों के शामिल होने की संभावना जताई गई थी। इस हमले के परिणामस्वरूप कार्गो प्रबंधन डेटा बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिससे कंटेनर खो गए, गलत डिलीवरी हुई और कंपनी को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।

इस प्रकार, यह स्पष्ट होता है कि समुद्री उद्योग में साइबर हमलों की घटनाएँ केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, समुद्री व्यापार की निरंतरता और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती हैं।

फिर 2016में, दक्षिण कोरिया ने उतर कोरिया पर अपनी सीमाओ के पास जीपीएस जैमिंग हमलों का उपयोग करने का आरोप लगाया, जिससे जहाज ओर विमान दोनों प्रभावित हुए। जीपीएस मुद्दों के कारण लगभग 280 जहाज बंदरगाह पर लौट आए एक साल बाद,2017 में दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में से एक, मैसर्क, नॉटपेटया रेनसमवेयर की चपेट में आ गई, जिससे कंपनी के दुनिया भर के कारोबार प्रभावित हुए ओर 300मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान हुआ। नॉटपेटया रेनसमवेयर शुरू में यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाले टैक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मैडॉक के जरिए फैला ओर फिर दुनिया भर में फैल गया, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ (शर्मा,2024)।

चीन की भूमिका और प्रतिक्रिया

चीन अपनी नीतियों को तर्कसंगत और स्वाभाविक मानता है, क्योंकि वह हिंद–प्रशांत क्षेत्र में अपनी केंद्रीयता स्थापित कर वैश्विक व्यवस्था में शीर्ष स्थान प्राप्त करना चाहता है। क्वाड के प्रति उसकी प्रतिक्रिया दो स्तरों पर दिखाई देती है - **प्रत्यक्ष** और **अप्रत्यक्ष**। प्रत्यक्ष रूप में, चीन ने क्वाड को शीत युद्ध जैसी मानसिकता वाला गठबंधन बताया और इसे तुरंत अस्वीकार कर दिया। वहीं अप्रत्यक्ष रूप में, उसने अपने नेतृत्व में एक वैकल्पिक क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने की रणनीति अपनाई, जिसमें बेल्ट एंड रोड पहल और क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी जैसे ढांचे शामिल हैं। इस संदर्भ में चीन की नीति में सॉफ्ट पॉवर और वास्तविक राजनीति के मिश्रण को दर्शाती है। चीन एक ओर सहयोग और शांति की बात करता है, पर दूसरी ओर वह अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए सामरिक और आर्थिक दबाव का प्रयोग करता है।

अतः चीन की प्रतिक्रिया विरोधाभासी प्रतीत होती है, जहाँ वह साझेदारी का संदेश देता है, वहीं समानांतर रूप से क्वाड के प्रभाव को सीमित करने और क्षेत्रीय व्यवस्था में अपनी प्रधानता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है (जाफरी एवं परवेज, 2023)। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का मुख्य उद्देश्य सड़कों, रेलमार्गों, बंदरगाहों, संचार नेटवर्क और ऊर्जा परियोजनाओं जैसी अवसंरचनाओं के माध्यम से विभिन्न देशों और क्षेत्रों को आपस में जोड़ना है। यह पहल केवल आर्थिक संपर्क का साधन नहीं, बल्कि चीन की व्यापक भू–राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी है।

इस परियोजना के तीन प्रमुख मार्ग हैं –

1. मध्य एशिया से होकर रूस के माध्यम से बाल्टिक सागर तक,
2. मध्य एशिया से पश्चिम एशिया होते हुए फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर तक,
3. दक्षिणी चीन से दक्षिण–पूर्व एशिया होते हुए दक्षिण एशिया और अंततः हिंद महासागर तक।

राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने इस पहल के अंतर्गत अधिक अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक वस्तुएँ उपलब्ध कराने, भूमि और समुद्री परियोजनाओं को वित्तीय सहयोग देने, तथा अवसंरचना विकास को प्रोत्साहित करने की बात कही। इसके लिए उन्होंने सिल्क रोड फंड में 40 अरब डॉलर देने की घोषणा की।

आतंकवाद का मुकाबला

क्वाड देशों ने वैश्विक आतंकवाद को अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा मानते हुए वर्ष 2023 में आतंकवाद–निरोधक कार्य समूह (काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप-सी.टी.डब्ल्यू.जी.) की स्थापना की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करना, सूचनाओं का आदान–प्रदान बढ़ाना, और रणनीतिक संवाद के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है।

यह कार्य समूह मानव रहित हवाई प्रणालियों (सी–यू.ए.एस.), रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सी.बी.आर.एन.) खतरों, तथा इंटरनेट के माध्यम से फैलने वाले उग्रवाद जैसे समकालीन मुद्दों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। इसके अंतर्गत क्वाड देश तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं और आतंकवाद–विरोधी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के माध्यम से अन्य देशों को भी इस सहयोग ढांचे से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

यह पहल न केवल क्वाड की वैश्विक सुरक्षा के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है, बल्कि यह इस बात का भी संकेत देती है कि हिंद–प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता के लिए आतंकवाद–विरोधी सहयोग अब उसकी रणनीतिक प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान प्राप्त कर चुका है (क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन तथ्य पत्रक, 2024)।

निष्कर्ष

भारत की हिन्द–प्रशांत नीति, जो पहले सीमित और निष्क्रिय मानी जाती थी, अब इक्कीसवीं सदी के बदलते भू–राजनीतिक परिदृश्य में एक सक्रिय, दूरदर्शी और समग्र रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में उभरी है। प्रारंभ में यह नीति केवल हिंद महासागर क्षेत्र तक सीमित थी, किंतु समय के साथ इसका विस्तार प्रशांत महासागर तक हो गया। इस परिवर्तन के पीछे अमेरिका की एशिया पुनर्संतुलन नीति जैसी बाहरी प्रेरणाओं के साथ-साथ भारत की अपनी समुद्री सुरक्षा, आर्थिक संभावनाओं और रणनीतिक हितों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है।

भारत का दृष्टिकोण किसी शक्ति प्रतिस्पर्धा या क्षेत्रीय प्रभुत्व की भावना पर आधारित नहीं है। इसके विपरीत भारत इस बात पर बल देता है कि क्षेत्र के सभी देश समानता, सहयोग और परस्पर सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित होकर प्राकृतिक संसाधनों और समुद्री मार्गों का न्यायपूर्ण उपयोग करें। भारत की यह नीति शांति, स्थिरता और साझा विकास पर केंद्रित है। इसी सोच के अंतर्गत भारत एकल और सामूहिक दोनों प्रकार की रणनीतियों को अपनाने के लिए तत्पर है, ताकि अपने राष्ट्रीय हितों के साथ-साथ क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाए रख सके।

हिन्द-प्रशांत की अवधारणा का एक प्रमुख स्तम्भ बहुपक्षीयता का मजबूत करना है| 2007 में गठित क्वाड समूह, जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस समूह की मूल भावना समुद्री सुरक्षा, सहयोग और आपदा प्रबंधन पर केंद्रित रही है। 2008 में, ऑस्ट्रेलिया की असहमति के कारण यह मंच निष्क्रिय हो गया था, किंतु चीन की बढ़ती आक्रामक नीतियों, दक्षिण चीन सागर में उसकी प्रभुत्ववादी गतिविधियों और बेल्ट एंड रोड पहल जैसी परियोजनाओं ने 2017 में, इसके पुनर्जीवन को संभव बनाया। इस पुनःस्थापना ने यह स्पष्ट किया कि समान विचारधारा वाले देशों को मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता और नियम आधारित व्यवस्था की रक्षा करनी होगी।

क्वाड को केवल एक सैन्य गठबंधन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह एक ऐसा मंच है जो लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शी विकास और साझा सुरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य हिंद–प्रशांत क्षेत्र में समुद्री स्वतंत्रता, न्यायपूर्ण व्यापार, पर्यावरणीय संतुलन और आपसी सहयोग को सशक्त बनाना है।

इस परिप्रेक्ष्य में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत को अपनी समुद्री क्षमताओं और नौसैनिक शक्ति को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि वह आपदा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा और मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा सके। साथ ही भारत को साझेदारी आधारित कूटनीति को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग की भावना को बल मिले। क्वाड के साथ-साथ भारत को आसियान, बिम्सटेक और आयोरा जैसे अन्य क्षेत्रीय मंचों के साथ भी सामंजस्य बनाकर बहुस्तरीय रणनीति पर कार्य करना चाहिए।

भारत को तकनीकी और आर्थिक सहयोग को भी अपनी विदेश नीति के केंद्र में रखना चाहिए ताकि सतत विकास और आपूर्ति शृंखलाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। यह नीति तभी सफल होगी जब भारत अपनी हिन्द–प्रशांत रणनीति को एक्ट ईस्ट नीति और सागर दृष्टि के साथ समन्वित रूप से आगे बढ़ाए। इस प्रकार भारत एक जिम्मेदार, संतुलित और प्रभावशाली समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित हो सकेगा।

अंततः यह कहा जा सकता है कि भारत की हिन्द–प्रशांत नीति केवल एक भौगोलिक अवधारणा नहीं, बल्कि यह भारत की व्यापक सोच, लोकतांत्रिक मूल्यों और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है। भारत इस क्षेत्र में न तो किसी शक्ति के विरोध

में कार्य कर रहा है और न ही प्रभुत्व की खोज में है, बल्कि वह उस सहयोग और सहभागिता की भावना को सशक्त कर रहा है जो इक्कीसवीं सदी की अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करेगी।

संदर्भ सूची

- जाफ़री, टी., एवं परवेज़, एम. एस. (2023). चीन की प्रतिक्रिया क्वाड के प्रति हिंद-प्रशांत क्षेत्र में: एक विरोधाभासी रणनीति? *स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, 47*(4), 363–375. https://doi.org/10.1080/09700161.2023.2263702
- सरकार, एम. जी. (2020). चीन और क्वाड 2.0: प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय पुनर्निर्माण के बीच. *मैरीटाइम अफेयर्स: जर्नल ऑफ द नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन ऑफ इंडिया, 16*(1), 110–130. https://doi.org/10.1080/09733159.2020.1794526
- सुलिवन, डी., एवं एस्ट्राडा, के. (2023). भारत और हिंद-प्रशांत में व्यवस्था परिवर्तन: 'सुरक्षा समुदाय' के रूप में क्वाड का प्रतिरोध. *द पैसिफिक रिव्यू, 36*(2), 378–405. https://doi.org/10.1080/09512748.2022.2160792
- पंत, एच. वी., एवं रेज, ए. (2018). क्या भारत हिंद-प्रशांत के लिए तैयार है? *द वॉशिंगटन क्वार्टरली, 41*(2), 47–61. https://doi.org/10.1080/0163660X.2018.1485403
- भारत सरकार, विदेश मंत्रालय. (2024, 21 सितंबर). *तथ्य पत्र: 2024 क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन.* https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/38327/Fact_Sheet_2024_Quad_Leaders_Summit
- डी कास्त्रो, आर. सी. (2021). क्वाड का पुनरुत्थान और हिंद-प्रशांत का उदय: 21वीं सदी का भू-राजनीतिक क्षेत्र. *एडीआर.* https://www.adrinstitute.org/article/quad-indo-pacific
- सेन, ए. (2023). भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका और उसका हिंद-प्रशांत से संबंध. *जादवपुर जर्नल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, 27*(1), 105–127. https://doi.org/10.1177/09735984231164457
- शर्मा, एल. (2024). हिंद-प्रशांत में समुद्री साइबर सुरक्षा: क्वाड की संभावित भूमिका का विश्लेषण. *जर्नल ऑफ द इंडियन ओशन रीजन, 20*(1), 14–36. https://doi.org/10.1080/19480881.2024.2341467
- अली, जी. (2023). सीमा विवाद, नेताओं की भूमिका और क्वाड का प्रभाव: चीन-भारत सीमा तनावों का त्रिकोणीय विश्लेषण. *द पैसिफिक रिव्यू, 37*(3), 533–555. https://doi.org/10.1080/09512748.2023.2185662
- कोल्माश, एम., क़ियाओ-फ्रैंको, जी., एवं कर्माज़िन, ए. (2024). निकटता, हितों और पहचान के माध्यम से क्षेत्र निर्माण की समझ: हिंद-प्रशांत को एक क्षेत्रीय परिभाषा के रूप में पुनर्विचार. *द पैसिफिक रिव्यू, 37*(6), 1067–1089. https://doi.org/10.1080/09512748.2023.2300976
- फेंग, हुईयुन. (2020). हिंद-प्रशांत का संस्थानीकरण: समस्याएँ और संभावनाएँ. *इंटरनेशनल अफेयर्स, 96*(1), 149–168. https://doi.org/10.1093/ia/iiz194
- दोराइबाबू, एम. (2020). पुस्तक समीक्षा: *द कॉस्टलियस्ट पर्ल: चाइना'ज़ स्ट्रगल फॉर इंडिया'ज़ ओशन* (बर्टिल लिंटनर द्वारा). *जर्नल ऑफ डिफेंस स्टडीज़.*